भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2557
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

अवर स्नातक रोजगार सृजन योजना

2557. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अवर स्नातक रोजगार सृजन योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्नातक करने वाले छात्रों को कोई प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या युवाओं की रोजगार क्षमता में 2014 से कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से, युवाओं सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करना है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ युवाओं की नियोज्यता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्व-निधि योजना) आदि जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है। सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, नौकरी बाजार में औपचारिकता को बढ़ावा देने और नियोज्यता में सुधार के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।

(ग) कुशल भारत मिशन (एसआईएम) देश के युवाओं के लिए भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। पीएमकेवीवाई के तहत, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) की स्थापना के माध्यम से व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है, जिसमें अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा है। सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रौद्योगिकी-संचालित पाठ्यक्रम को एकीकृत किया है, जो कृत्रिम मेधा (एआई), ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, उद्योग स्व-चालन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। आईआईटी और निजी तकनीकी कंपनियों जैसे संस्थानों के साथ सहयोग उभरती प्रौद्योगिकियों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण को सुनिश्चित करता है। पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल और मिश्रित प्रशिक्षण प्रारूप अपनाए जा रहे हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 31 आधुनिक या भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उच्च मांग वाली भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफ़एस 2023-24) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 10.2 प्रतिशत हो गई है। 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गया है।

*****